एन. कस्तूरी

बनाम

डी. पोन्नामल और अन्य

23 फरवरी 1961

[पी.बी. गजेंद्रगढ़कर और के.एन. वांचू, जे.जे.]

वसीयत- का निर्माण- गोद न लेने की स्थिति में 'के' के नाम वसीयत करना- 'के' को गोद का वसीयतकर्ता का इरादा- गोद लेने का अधिकार विधवा को दिया गया- गोद नहीं लिया गया- 'के' के अधिकार, क्या गोद लेने के बाद निहित हित विफल हो जाएगा।

एक वसीयतकर्ता, जो निःसंतान था, ने 28 अप्रैल 1937 को एक वसीयत निष्पादित की, और 10 मार्च 1939 को उनकी मृत्यु हो गई, अपने पीछे वे अपनी पत्नी को छोड़ गए। वसीयत के खंड 6 में उन्होंने एक लड़के को गोद लेने की इच्छा जताई और कहा कि यदि वह अपने जीवन काल में गोद नहीं पाता है तो उसकी पत्नी 'के' को गोद ले लेगी। उसने अपनी पत्नी को यह अधिकार भी प्रदान किया कि यदि गोद लेने से पहले 'के' की मृत्यु हो जाती है तो भी उसकी पत्नी को गोद लेना होगा। वसीयत के खंड 11 द्वारा उन्होंने प्रावधान किया कि उन संपत्तियों को छोड़कर जो टी. की पत्नियों, एम. ए. और के. ए., और बेटी के लिए और उसकी पत्नी के लिए दी जा सकती हैं ताकि प्रत्येक अपने जीवनकाल के दौरान इसका आनंद ले सके। उनके परिवार की शेष सभी संपत्तियों में से आधे के संबंध में, उनकी पत्नी को गोद लेने से पहले, के.एस. के पक्ष में एक दस्तावेज निष्पादित करना होगा जिसके तहत वह अपने जीवनकाल के दौरान

केवल उन संपत्तियों से आय प्राप्त करेंगे और यह कि उसके जीवनकाल के बाद उसके उत्तराधिकारियों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे, और वह इस आशय की व्यवस्था भी करेगी कि उसके दत्तक पुत्र को भी इसी तरह शेष आधा हिस्सा मिले। खंड 12 में प्रावधान है: "यदि मैं और मेरी पत्नी बिना गोद लिए मर जाएं या मेरी पत्नी पहले ही मर जाए या यदि मैं किसी लड़के को गोद नहीं लेता हूं या मेरे द्वारा गोद लिया गया लड़का मेरी मृत्यु के समय जीवित नहीं है, तो उपरोक्त 'के' और उपरोक्त 'के. एस.' को मेरी सारी संपत्ति समान हिस्सों में मिलेगी..... यदि मैं और मेरी पत्नी ऊपर बताए अनुसार गोद लिए बिना मर जाते हैं और यदि उपरोक्त 'के. एस.' हमसे पहले ही मर जाता है, तो उपरोक्त 'एम. ए.' और 'के. ए.' को सारी संपत्ति मिल जाएगी....."

वसीयतकर्ता द्वारा उसकी मृत्यु से पहले या उसके बाद उसकी विधवा द्वारा कोई गोद नहीं लिया गया था। 'के' ने वसीयत के तहत अपने अधिकारों की घोषणा के लिए खंड 12 के तहत अपने दावे को इस आधार पर दायर किया कि उस खंड के तहत जब कोई गोद नहीं लिया गया था और जब तक ऐसा नहीं किया गया था तब तक उसके पास बाद में गोद लेने के अधीन आधी संपत्तियों के संबंध में निहित अधिकार था।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 28 अप्रैल, 1937 की वसीयत के वास्तविक निर्माण पर, खंड 12 का उद्देश्य वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय लागू होना था, बाद में नहीं और 'के' को उस खंड के तहत अधिकार केवल तभी मिलेगा जब उसकी विधवा की वसीयतकर्ता से पहले ही मृत्यु हो जाती और उसकी मृत्यु से पहले वसीयतकर्ता द्वारा कोई गोद नहीं लिया गया था। इन परिस्थितियों में 'के' के अधिकार केवल खंड 11 द्वारा प्रदान किए गए थे और वे अधिकार तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकते थे जब तक कि उसे विधवा द्वारा गोद नहीं लिया जाता। इस दृष्टिकोण पर निहितीकरण का स्थगन और निर्वसीयत की संभावना थी, लेकिन उसे टाला नहीं जा सकता था।

निहितार्थ के स्थगन और निर्वसीयता से बचने के खिलाफ वसीयत के निर्माण के नियम पूर्ण नहीं हैं और न्यायालय किसी पूर्वकल्पित धारणा के साथ वसीयत बनाने के कार्य को शुरू नहीं कर सकती है कि निर्वसीयत को टाला जाना चाहिए या निर्वसीयत को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

वसीयतकर्ता के इरादे को वसीयत को समग्र रूप से समझकर और वसीयत में संबंधित खंडों को उनके स्पष्ट व्याकरणिक अर्थ देकर एक साथ विचार करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ज्ञानम्बल अम्मल बनाम टी. राजू अय्यर और अन्य, ए.आई.आर. 1951 एस.सी. 103 और वेंकट नरसिम्हा बनाम पार्थसारथी, एल. आर. 41 आई.ए. 51 संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 373/1956

ए.एस. संख्या 270/1948 में मद्रास उच्च न्यायालय के 17 सितंबर 1952 के फैसले और डिक्री से अपील।

अपीलार्थी की ओर से ए.वी. विश्वनाथ शास्त्री, ए.वी. नारायणस्वामी और एमएस नरसिम्हन टीके सुंदर रमन के लिए।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए एम.सी. सीतलवाड, अटॉर्नी-जनरल, आर. राममूर्ति अय्यर और बी.के.बी. नायडू।

आर. राममूर्ति अय्यर और बी.के.बी. नायडू, प्रतिवादी संख्या 2 और 4 और प्रतिवादी संख्या 5 के कानूनी प्रतिनिधियों के लिए।

23 फरवरी, 1961। न्यायालय का फैसला गजेंद्रगडकर, जे. द्वारा सुनाया गया। यह अपील 28 अप्रैल, 1937 को वसीयतकर्ता दिरवियाम पिल्लई द्वारा निष्पादित वसीयत के निर्माण के बारे में एक संक्षिप्त प्रश्न उठाती है, और यह मदुरा में अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में अपीलकर्ता एन. कस्तूरी द्वारा दायर मुकदमे से उत्पन्न होती है। अपने मुकदमे में अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि वसीयत के खंड 12 के तहत उसमें वर्णित संपत्ति के संबंध में उसे निहित या आकस्मिक कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे और उक्त अधिकारों के अनुसरण में उसने अपने हितों की रक्षा करने और संपत्ति को बर्बाद होने से बचाने और वसीयतकर्ता की विधवा, प्रतिवादी 1, पोन्नम्मल, जो उक्त संपत्ति की प्रभारी थी, के हाथों खोने से बचाने के लिए एक घोषणा का दावा किया था। विचारण न्यायालय ने वसीयत को अपीलकर्ता के खिलाफ माना और अभिनिर्धारित किया कि इसने उसे कोई अधिकार नहीं दिया, और इसलिए वह अपनी याचिका में निर्धारित किसी भी राहत का दावा नहीं कर सकता था। संयोग से, गुण-दोष के आधार पर विचारण न्यायालय इस बात से संतुष्ट था कि अपीलकर्ता द्वारा एक मामला बनाया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि संपत्ति को उसके वर्तमान धारक, प्रतिवादी 1 द्वारा बर्बाद किया जा रहा था। फिर अपीलकर्ता ने अपनी अपील के माध्यम से मामले को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रखा। उच्च न्यायालय ने वसीयत के निर्माण में विचारण न्यायालय से सहमति जताई है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता के पास वसीयत के तहत कोई अधिकार नहीं था जो उसके वादपत्र में निर्धारित किसी भी राहत के लिए उसके दावे को उचित ठहराता हो। उस निष्कर्ष पर उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अस्वीकार किए गए मामले के गुण दोषों पर विचार करना अनावश्यक समझा। अपीलकर्ता ने तब एक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और उच्च न्यायालय से वह प्रमाण पत्र प्राप्त किया, और उक्त प्रमाणपत्र के साथ वह अपनी वर्तमान अपील के द्वारा इस न्यायालय में

आया है; और इसलिए, हमारे निर्णय के लिए एकमात्र प्रश्न यह है: क्या विचारण न्यायालयों ने वसीयत पर अनुचित निर्माण किया है जैसा कि अपीलकर्ता के लिए श्री विश्वनाथ शास्त्री का तर्क है?

जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि वसीयतकर्ता ने 28 अप्रैल, 1937 को वसीयत निष्पादित की और 10 मार्च, 1939 को उनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवनकाल के दौरान वसीयतकर्ता एक संयुक्त और अविभाजित हिंदू परिवार का सदस्य था, जिसमें वह और उसका चचेरा भाई थायुमानस्वामी पिल्लई शामिल थे। दोनों में से किसी का कोई बेटा नहीं था। 9 मई 1935 को हुई उनकी मृत्यु के समय, थायुमानस्वामी पिल्लई अपने पीछे दो विधवाएँ, प्रतिवादी 2, मंगयारकारसी अम्मल और प्रतिवादी 3, कन्नियाम्मल, और पूर्व प्रतिवादी की बेटी प्रतिवादी 4, पिचाई अम्मल को छोड़ गए। वसीयतकर्ता जो अपने चचेरे भाई के जाने के बाद परिवार की पूरी संपत्ति का हकदार हो गया, और यह इस प्रकार है कि उसने प्रश्नगत वसीयत बनाई, और वह उसे बनाने में सक्षम था। अपीलकर्ता वसीयतकर्ता की बहन की बेटी का पोता है, जबकि कल्याणसुंदरम, प्रतिवादी 5, को वसीयतकर्ता के चचेरे भाई, थायुमानस्वामी पिल्लई ने पालक-पुत्र के रूप में माना था। प्रतिवादी 5 की मृत्यु इस न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान हो गई और वह अपने पीछे दो विधवाएँ, दो नाबालिग बेटे और दो नाबालिग बेटियाँ छोड़ गया, जिन्हें उसके उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है। ये वे व्यक्ति हैं जिनका उल्लेख वसीयत में किया गया है और जो किसी न किसी रूप में वसीयतकर्ता की संपत्ति के पात्र प्रतीत होते हैं।

अब वसीयत को सामान्य रूप से संदर्भित करना और दोनों खंडों को पढ़ना आवश्यक है जो विशेष रूप से वर्तमान अपील में समझे जाते हैं। वसीयत का खंड 1 इस तथ्य को संदर्भित करता है कि वसीयतकर्ता ने पहले ही 12 जून, 1935 को एक

वसीयत निष्पादित कर दी थी और इसे पंजीकृत करा लिया था। वर्तमान वसीयत उसके द्वारा अपनी पिछली वसीयत को रद्द करने और वर्तमान वसीयत में निर्दिष्ट अपनी संपत्ति के संबंध में नई व्यवस्था करने के उद्देश्य से निष्पादित की गई थी।

वसीयत के खंड 2 में कहा गया है कि वसीयतकर्ता और उसके वरिष्ठ चचेरे भाई, मृतक थायुमनस्वामी पिल्लई, एक अविभाजित हिंदू परिवार के सदस्य थे और इस तरह उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी और उन दोनों के नाम पर धन उधार देने का व्यवसाय किया था। वसीयतकर्ता आगे कहता है कि उसके चचेरे भाई की मृत्यु पर, एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी के रूप में वह पूरी संपत्ति का पूर्ण मालिक बन गया।

खंड 3 में कहा गया है कि वसीयतकर्ता तब 64 वर्ष का था और उसे और उसकी पत्नी, प्रतिवादी 1 को कोई समस्या नहीं थी। फिर वह अपने अन्य संबंधों का हवाला देता है जो उससे संबन्धित थे।

खंड 4 में वसीयतकर्ता बताता है कि परिस्थितिवश पारिवारिक संपत्ति के संबंध में व्यवस्था करना आवश्यक था "ताकि मेरे जीवनकाल के बाद परिवार में किसी भी तरह का विवाद या झगड़ा न हो और पारिवारिक मामले मेरी इच्छा के अनुसार चल सकें।" यह मामला, कई अन्य मामलों की तरह, दर्शाता है कि वसीयतकर्ता द्वारा व्यक्त की गई आशा और अपेक्षा कि उसकी वसीयत बनाने से मुकदमेबाजी और विवादों को रोका जाना चाहिए, सच नहीं हुई है।

खंड 5 वसीयत के विघटनकारी खंडों की प्रस्तावना की प्रकृति में है और इस प्रकार है। इसमें कहा गया है कि उनके मृत चचेरे भाई ने अपने जीवनकाल के दौरान संपत्तियों के संबंध में कुछ इच्छा व्यक्त की थी, और वसीयतकर्ता उनकी इच्छाओं के

सम्मान में उक्त इच्छाओं के अनुरूप और उसके अनुसार वसीयत में निर्धारित व्यवस्था कर रहा था।

खंड 6 इस घोषणा से शुरू होता है कि वसीयतकर्ता अपने परिवार की वंश वृद्धि के लिए एक लड़के को गोद लेना चाहता था; और इसमें कहा गया है कि यदि वसीयतकर्ता ने अपने जीवनकाल के दौरान गोद नहीं लिया है तो उसकी पत्नी, प्रतिवादी 1, अपीलकर्ता को गोद लेगी। इसके बाद इस खंड में कहा गया है कि यदि अपीलकर्ता को गोद लेने से पहले वह ईश्वरेच्छया से मर जाये तो वसीयतकर्ता ने अपनी पत्नी को अनुमति दी और उसे अपने समुदाय से एक और अच्छे और उपयुक्त लड़के को गोद लेने के लिए अधिकृत किया; और एहतियात के तौर पर वसीयतकर्ता अपनी पत्नी द्वारा गोद लिए गए लड़के की मृत्यु की संभावना के विषय में भी बात करता है और उसे बाद में भी फिर से गोद लेने के लिए अधिकृत करता है।

इस प्रकार वसीयत के खंड 6 में वसीयतकर्ता की स्वयं गोद लेने की इच्छा व्यक्त की गई है और यदि वह अपने जीवनकाल में गोद नहीं लेता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को इस प्रकार गोद लेने का अधिकार देता है।

यदि दत्तक पुत्र अवयस्क है तो खंड 7 संपत्ति के प्रबंधन का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि दत्तक पुत्र के अवयस्क होने के दौरान उसकी पत्नी उसकी संरक्षिका होगी और केवल अपनी वसीयत में उसके द्वारा निर्दिष्ट सलाहकारों से संपत्तियों के प्रबंधन और अन्य पारिवारिक मामलों के संबंध में आवश्यक सलाह लेगी। दत्तक पुत्र के वयस्क होने पर उसे संपत्तियां दत्तक पुत्र को सौंपने का निर्देश दिया गया है। वसीयतकर्ता यह स्पष्ट करता है कि दत्तक पुत्र इस प्रकार प्राप्त संपत्तियों को सूदखोरी बंधक, साधारण बंधक, बिक्री आदि के अधीन किए बिना उनका उपभोग करेगा और उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को वह संपत्ति पूर्ण अधिकार के साथ मिलेगी।

इस प्रकार वसीयतकर्ता ने अपने दत्तक पुत्र को आजीवन सम्पदा प्रदान की है और संपत्ति पूरी तरह से दत्तक पुत्र के उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दी है।

खंड 8 के अनुसार यदि गोद लिए बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो वसीयतकर्ता अपनी पत्नी को अपनी वसीयत का निष्पादिका बनाता है; और यह उसे उस संबंध में वसीयत के प्रावधानों को पूरा करने और उसके द्वारा निर्दिष्ट सलाहकारों से आवश्यक सलाह लेने की शक्तियां प्रदान करता है। यह खंड निष्पादक को उसके द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार एक लड़के को गोद लेने, लड़के के वयस्क होने तक संपत्ति का प्रबंधन करने और उसके वयस्क होने पर संपत्ति उसे सौंप देने के लिए निम्नलिखित खंडों के तहत विस्तार से उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों को प्रतिवादीगण 2, 3, 4 और 5 के पक्ष में निष्पादित करने का दायित्व देता है। इस खंड में निर्धारित अपने दायित्वों के निर्वहन में उसे सलाहकारों से परामर्श करने और अपने कर्तव्यों को "विधिवत और ठीक से" पूरा करने के लिए कहा गया है। इस खंड में वसीयतकर्ता ने अपने अधिदान की वस्तुओं को इंगित किया है और वसीयत में निर्दिष्ट प्रकृति को पूरा करने के लिए निष्पादिका पर दायित्व लगाया है।

खंड 9 प्रतिवादीगण 2, 3 और 4 के पक्ष में प्रबंध से संबंधित है। प्रतिवादी 4 के संबंध में वसीयतकर्ता ने विशेष आग्रह व्यक्त किया है क्योंकि वह युवावस्था में ही विधवा हो गई थी और वह चाहता था कि परिवार की स्थिति के अनुरूप उसके जीवनकाल के दौरान उसके भरण-पोषण के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि वह बिना किसी कठिनाई के अपना भरण-पोषण कर सके। इस खंड में निहित निर्देश यह दर्शाता है कि वसीयतकर्ता चाहता था कि तीनों प्रतिवादियों को उनके भरण-पोषण के लिए अलग-अलग संपत्तियां इस शर्त के साथ प्राप्त हों कि वे अपने जीवनकाल के दौरान

उक्त संपत्तियों को बिक्री, सूदखोरी बंधक, साधारण के अधीन किए बिना उनका आनंद लेंगे।

खंड 10 प्रतिवादी 5 से संबंधित है। प्रतिवादी 5 दिवंगत मुथुस्वामी पिल्लई की पहली पत्नी का बेटा है जो प्रतिवादी 4 का पति और प्रतिवादी 2 की बहन का बेटा था। वसीयतकर्ता के चचेरे भाई थायुमानस्वामी पिल्लई ने उनके साथ अपने अभिमानपुत्र (पालक पुत्र) जैसा व्यवहार किया था और उक्त चचेरे भाई की इच्छा थी कि वह उसे संपत्ति दे, जिस इच्छा से वसीयतकर्ता सहमत हो गया था। इस इच्छा के अनुसरण में वसीयतकर्ता आगामी खंडों में प्रतिवादी 5 के पक्ष में एक निर्णय देने के लिए आगे बढ़ा। वह खंड 10 का प्रभाव है। खंड 11 और 12 ऐसे खंड हैं जिनका अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसलिए अब हम उन्हें विस्तार में पढ़ेंगे:

> "खंड 11. विशेष संपत्तियाँ जो लिखित रूप में दी जा सकती हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्वर्गीय थायुमनस्वामी पिल्लई की पत्नियों और बेटी को और इसी तरह खुद के लिए, यानी मेरी पत्नी के लिए, प्रत्येक के जीवनकाल के दौरान आनंद लेने के लिए एक के संबंध में मेरे परिवार की शेष सभी संपत्तियों में से आधी, मेरी पत्नी, गोद लेने से पहले, उपरोक्त कल्याणसुंदरम के पक्ष में उपयुक्त विवरण के साथ एक दस्तावेज निष्पादित करेगी कि वह उन पर कोई भी भार डाले बिना, यानी किसी भी बिक्री, सूदखोरी बंधक, साधारण बंधक आदि किए बिना केवल उस आय का आनंद लेगा जो उसके जीवनकाल के दौरान प्राप्त हो सकती है और यह कि उनके जीवनकाल के बाद, उनके उत्तराधिकारियों को उस संपत्ति पर पूर्ण अधिकार मिलेगा और, वह हमेशा इस आशय की व्यवस्था करेगी कि मेरे दत्तक पुत्र को भी इसी

तरह संपत्ति का शेष आधा हिस्सा मिले। मेरी पत्नी पोन्नम्मल भी कल्याणसुंदरम के वयस्क होने तक उपरोक्त संपत्तियों में से आधे का प्रबंधन स्वयं करेंगी, और जैसे ही वह वयस्क हो जाएगा, वह ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुसार उसके उपभोग के लिए उसे देय संपत्तियां उसे सौंप देगी। जबकि स्वर्गीय थायुमानस्वामी पिल्लई की पत्नियों, बेटी पिचम्मल और मेरी पत्नी पोन्नम्मल के भरण-पोषण के लिए संपत्तियों को बाँट दिया गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दस्तावेजों में इसका उल्लेख किया जाएगा कि उनके जीवनकाल के बाद, उपरोक्त संपत्तियों को उपरोक्त कल्याणसुंदरम और मेरे या मेरी पत्नी द्वारा गोद लिए गए लड़के द्वारा समान हिस्सों में लिया जाएगा, या संबंधित व्यक्तियों की मृत्यु पर उनके संबंधित पुरुष उत्तराधिकारी, यदि कोई हों, उनके संबंधित आधे हिस्से के उत्तराधिकारी होंगे और यदि उनमें से कोई एक पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है और दूसरा अकेला जीवित रहता है तो ऐसा उत्तरजीवी अकेले ही दोनों हिस्से ले लेगा।

खंड 12. यदि मैं और मेरी पत्नी बिना गोद लिए मर जाएं या मेरी पत्नी पहले ही मर जाए या मैं किसी लड़के को गोद नहीं लेता हूं या मेरे द्वारा गोद लिया गया लड़का मेरी मृत्यु के समय जीवित नहीं है, उपरोक्त कस्तूरी और उपरोक्त कल्याणसुंदरम को उपरोक्त पैराग्राफ 11 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आनंद लेने के लिए मेरी संपूर्ण संपत्ति समान हिस्सों में मिलेगी और जैसा कि ऊपर बताया गया है, भरण-पोषण के लिए अलग रखी जाने वाली संपत्तियों से संबंधित शर्तों के अधीन होगी। यदि मैं और मेरी पत्नी ऊपर बताए अनुसार गोद लिए

बिना मर जाते हैं और उपरोक्त कल्याणसुंदरम हमसे पहले ही मर जाता है, तो उपरोक्त मंगयारकारसी अम्मल और कन्नियाम्मल को सारी संपत्ति मिल जाएगी और वे अपने जीवनकाल के दौरान किसी भी तरह की बाध्यता के बिना उनका आनंद लेंगे और मेरे द्वारा उन्हें एक लड़के को गोद लेने की अनुमति दी गई है, वे एक लड़के को गोद लेंगे और वह गोद लिया हुआ लड़का उनका उत्तराधिकारी होगा।"

इन खंडों का अर्थ निकालने से पहले हम वसीयत के शेष खंडों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं। खंड 13 वसीयतकर्ता द्वारा पहले से ही किए गए धर्मार्थ स्वभाव और उसके लिए उसके द्वारा की गई व्यवस्था को संदर्भित करता है। इसमें कहा गया है, "यहां तक कि अन्य दान के संबंध में भी, जो मैं इसके बाद करने का इरादा रखता हूं, संबंधित दस्तावेजों पर कार्रवाई की जाएगी।" खंड 14 में उन सलाहकारों का नाम दिया गया है, जिनके परामर्श से वसीयतकर्ता ने निष्पादिका को अपनी वसीयत की शर्तों को पूरा करने के लिए कहा है। खंड 15 के तहत वसीयतकर्ता यह प्रावधान करता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद या जब उसकी वसीयत प्रभावी होती है तभी उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए, तो प्रतिवादी 2 "परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त" प्रतिवादी 5 की निष्पादिका और संरक्षिका होगी। यदि प्रासंगिक समय पर वह भी जीवित नहीं है तो प्रतिवादी 3 को निष्पादिका और संरक्षिका होना चाहिए। खंड 16 में प्रावधान है कि यदि वसीयतकर्ता अपने जीवनकाल के दौरान गोद लिए बिना मर जाता है तो उसकी अंत्येष्टि प्रतिवादी 5 और अपीलकर्ता द्वारा की जाएगी; उक्त दो व्यक्तियों द्वारा ही उसकी पत्नी की अंत्येष्टि भी की जाएगी, यदि वह गोद लिए बिना मर जाती है, साथ ही प्रतिवादीगण 2 और 3 की अंत्येष्टि भी उनके द्वारा ही की जाएगी। प्रतिवादी 5 को प्रतिवादी 4 की अंत्येष्टि करनी होगी। खंड 17 में वसीयतकर्ता ने यह प्रावधान किया है कि यदि प्रतिवादी 2 या 3 वसीयतकर्ता बन जातीं हैं तो वह वसीयत में निर्दिष्ट सलाहकारों के

परामर्श से संपत्तियों का प्रबंधन करेगी। खंड 18 में वसीयतकर्ता ने प्रावधान किया कि उसकी वसीयत उसकी मृत्यु की तारीख से प्रभावी होगी और खंड 19 के द्वारा वसीयतकर्ता के पास अपनी वसीयत को बदलने या उसमें कुछ जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह वसीयत, जिसमें 19 खंड शामिल हैं, एक बहुत ही तर्कसंगत वसीयत है और यह उस परिवार के सभी व्यक्तियों के अधिकारों के साथ न्याय करना चाहती है, जो वसीयतकर्ता से संबन्धित थे और जिनके संबंध में एकमात्र जीवित सहृदायिक के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पहचाना। उसने ईमानदारी से अपने मृत चचेरे भाई की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास किया है, और कुल मिलाकर इसकी शर्तें बहुत निष्पक्ष और उचित हैं। हमारे निर्णय के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या अपीलकर्ता को वसीयत के खंड 12 के तहत कोई अधिकार मिलता है जो वर्तमान मुकदमे में उसके द्वारा की गई घोषणा और अन्य उचित राहत के लिए उसके दावे को उचित ठहराएगा? जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, दोनों ही निचली अदालतों ने अपीलकर्ता के खिलाफ इस प्रश्न का उत्तर दिया है।

श्री शास्त्री का तर्क है कि दो प्रासंगिक धाराओं की व्याख्या करते समय दो सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है जो वसीयत के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। पहला सिद्धांत यह है कि जहां तक उचित रूप से संभव हो न्यायालयों को वसीयत के उस निर्माण को अपनाना चाहिए जिससे निर्वसीयता से बचा जा सके; और दूसरा सिद्धांत यह है कि ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद संपत्ति के स्वामित्व को स्थगित कर देता है। पहले सिद्धांत के समर्थन में श्री शास्त्री ने सरोजिनी दासी वी. ज्ञानेंद्रनाथ दास और अन्य आदि ((1916) 23 कलकत्ता एल.जे. 241, 255) में मुखर्जी, जे. के अवलोकन पर भरोसा किया है। वसीयत में निहित कई प्रबंधों के निर्माण पर, जिनसे विद्वान न्यायाधीश निपट रहे थे, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त प्रबंधों को एक साथ समझने से पता चलता है कि वसीयतकर्ता का इरादा

अपनी सभी संपत्तियों का निपटान करने का था, फिर उन्होंने कहा, "यदि कोई संदेह है, तो हमें, यदि संभव हो तो, वसीयत को पढ़ना चाहिए ताकि वसीयतनामा हो सके, न कि निर्वसीयतनामा।" इस निष्कर्ष के समर्थन में विद्वान न्यायाधीश ने चार अंग्रेजी निर्णयों का उल्लेख किया, इन री रेडफर्न ((1877) 6 सीएच. डी 133), इन री हैरिसन ((1885) 30 सीएच. डी 390), किर्बी स्मिथ बनाम पार्नेल ([1903] 1 सीएच. 483) और इन री एडवर्ड्स ([1906] 1 सीएच. 570)। श्री शास्त्री द्वारा प्रतिपादित दूसरे सिद्धांत के समर्थन में उन्होंने बिकरस्टेथ और अन्य बनाम शानू ([1936] ए.सी. 290) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर भरोसा किया है। उस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अचल संपत्ति के साधनों की व्याख्या के लिए सुस्थापित नियम यह है कि उन्हें तब तक निहित माना जाता है जब तक कि निहित करने से पहले की कोई शर्त उचित स्पष्टता के साथ व्यक्त नहीं की जाती है।

दूसरी ओर, विद्वान अटॉर्नी-जनरल ने हमारा ध्यान ज्ञानम्बल अम्मल बनाम टी. राजू अय्यर और अन्य (ए.आई.आर. 1951 एस.सी. 103) मामले में इस न्यायालय के एक फैसले की ओर आकर्षित किया है, जिसमें इस न्यायालय ने निश्चित रूप से फैसला सुनाया है कि यदि दस्तावेज़ के संदर्भ या आसपास की परिस्थितियों से यह न्यायोचित है तो निर्वसीयतता के खिलाफ एक धारणा बनाई जा सकती है; लेकिन इसे केवल तभी लागू किया जा सकता है जब वसीयतकर्ता के इरादों के पता लगाने में निस्संदेह अस्पष्टता हो। मुखर्जी, जे., जैसा कि वह उस समय थे, ने देखा कि वसीयत को परिभाषित करने में न्यायालयों द्वारा पालन किया जाने वाला मुख्य नियम वसीयतकर्ता के इरादों को सुनिश्चित करने का प्रयास करना है। इस इरादे को मुख्य रूप से दस्तावेज़ की भाषा से पहचाना जाना चाहिए, जिसे किसी भी अनुमान या अटकल में शामिल किए बिना समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए कि अगर वसीयतकर्ता को और अच्छी जानकारी और बेहतर सलाह मिलती तो उसने क्या किया होता; और इस दृष्टिकोण के समर्थन में

विद्वान न्यायाधीश ने वेंकट नरसिम्हा बनाम पार्थसारथी ((1913) एल.आर. 41 आई.ए. 51, 70) में प्रिवी काउंसिल द्वारा की गई समान टिप्पणियों का हवाला दिया। इस सिद्धांत से निपटने में कि निर्वसीयता से बचा जाना चाहिए, मुखर्जी, जे. ने कहा कि निर्वसीयत से बचने की इच्छा अंग्रेजी आदतों पर आधारित थी जो भारतीय न्यायालय को बाध्य करे, यह जरूरी नहीं है। इसलिए, इसमें थोड़ा संदेह हो सकता है कि श्री शास्त्री ने निर्वसीयत से बचने के खिलाफ निर्माण के एक नियम के रूप में जो तैयार किया, उसे एक पूर्ण नियम के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसका वसीयत बनाने में अत्यधिक महत्व होना चाहिए। यदि दो निर्माण उचित रूप से संभव हैं, और उनमें से एक निर्वसीयत से बचता है जबकि दूसरे में निर्वसीयत शामिल है, तो न्यायालय निश्चित रूप से उस निर्माण को प्राथमिकता देगी जो निर्वसीयत से बचता है। इस नियम को उन मामलों में भी लागू करने की अनुमति दी जा सकती है जहां इस्तेमाल किए गए शब्द अस्पष्ट हैं और ऐसी संरचना को अपनाकर अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है जो निर्वसीयत से बचती है। इसी प्रकार, इस नियम के संबंध में कि निहितीकरण को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। यह स्पष्ट है कि कोई न्यायालय इस पूर्वकल्पित धारणा के साथ वसीयत तैयार करने का कार्य शुरू नहीं कर सकती है कि निर्वसीयतता से बचा जाना चाहिए या निहितार्थ को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। वसीयतकर्ता के इरादे और वसीयत में निहित प्रबंधों के प्रभाव को वसीयत को समग्र रूप से समझकर और वसीयत में संबंधित खंडों को उनके स्पष्ट व्याकरणिक अर्थ पर एक साथ विचार करके तय किया जाना चाहिए। किसी वसीयत का अर्थ निकालने में अन्य वसीयतों के निर्माण का उल्लेख करना आम तौर पर लाभदायक या उपयोगी नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक वसीयत का निर्माण आवश्यक रूप से वसीयत द्वारा उपयोग की गई शर्तों पर निर्भर होना चाहिए, जिसे समग्र रूप से माना जाता है और उक्त शब्दों के निष्पक्ष और उचित निर्माण पर जो परिणाम आता है

वह वसीयत से वसीयत तक भिन्न होना चाहिए। इसलिए, हमें संबंधित खंडों को ध्यान से देखना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि दोनों प्रतिद्वंद्वी निर्माणों में से किसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री शास्त्री ने तर्क दिया कि खंड 11 और 12 अलग और स्वतंत्र खंड हैं और वे दो अलग और भिन्न स्थितियों से संबंधित हैं।

उनके अनुसार खंड 11 उस स्थिति से संबन्धित है जो वसीयतकर्ता की विधवा द्वारा गोद लेने पर उत्पन्न होती, जबकि खंड 12 उस स्थिति से संबंधित है जो तब उत्पन्न होगी जब कोई गोद नहीं लिया जाएगा। उनका तर्क यह है कि जब कोई गोद नहीं लिया जाता है और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक अपीलकर्ता के पास आधी संपत्तियों के संबंध में एक निहित अधिकार होता है, जो निस्संदेह बाद में गोद लेने पर समाप्त हो सकता है। उनका तर्क है कि यह एक निहित अधिकार है जो बाद में गोद लेने के द्वारा विफल होने के अधीन है, और इस अधिकार का उस अधिकार से कोई लेना-देना नहीं है जो अपीलकर्ता को प्रदान किया जाएगा यदि उसे खंड 11 द्वारा किए गए विचार के अनुसार गोद लिया जाता है। अपीलकर्ता के अनुसार यह खंड 12 का आशय और प्रभाव है, और इस तरह अपीलकर्ता निर्वसीयतता और निहितार्थ के स्थगन से बचता है।

प्रतिवादियों का मामला, हालांकि, यह है, और यह वह मामला है जिसे नीचे की अदालतों द्वारा स्वीकार किया गया है, खंड 12 को वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय लागू माना जाना चाहिए और बाद में नहीं, और इस तर्क के अनुसार, जैसे ही वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई, उक्त खंड लागू होना बंद हो गया और अपीलकर्ता के अधिकार केवल खंड 11 के तहत माने जाएंगे। यदि खंड 12 को खंड 11 से अलग करके समझा जाता तो अपीलकर्ता द्वारा आग्रह किए गए विवाद के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता था;

लेकिन, हमारी राय में, खंड 12 को अकेले लेना और इसे बाकी वसीयत से अलग करना निर्माण के सभी नियमों के साथ स्पष्ट रूप से असंगत होगा। खंड 6 से 11 मुख्य रूप से गोद लेने से संबंधित है जिसके बारे में वसीयतकर्ता ने विचार किया था कि यदि उसने अपने जीवनकाल में गोद नहीं लिया तो उसकी विधवा द्वारा गोद लिया जाएगा। खंड 11 प्रतिवादी 5 को निहित अधिकार प्रदान करता है। यह प्रतिवादी 1 द्वारा गोद लेने से पहले किया जाना चाहिए और वास्तव में यह अपने आप में एक स्वतंत्र वसीयत है। फिर उक्त खंड अपीलकर्ता को संभावित रूप से गोद लिया गया मानता है और फिर उस स्तर पर उसके अधिकारों से निपटता है। उक्त खंड द्वारा की गई अन्य वसीयतों से हमारा सीधा संबंध नहीं है। इस प्रकार खंड 11 में इस आधार पर प्रावधान किए गए कि उसकी विधवा गोद ले सकती है, खंड 12 एक वैकल्पिक स्थिति से संबंधित है जो उक्त खंड द्वारा विचार किए गए मामलों में उत्पन्न होगी, और इसका उद्देश्य केवल वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय ही लागू होना है, अन्यथा नहीं। यदि यह सही स्थिति है तो अपीलकर्ता खंड 12 के तहत किसी भी अधिकार का हकदार नहीं होगा।

अब, निर्माण के मामले में अपीलकर्ता के मामले को स्वीकार करने में कुछ गंभीर कठिनाइयां हैं। खंड 12 का पहला भाग चार संभावित मामलों को संदर्भित करता है, वसीयतकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से गोद लेना, वसीयतकर्ता के जीवनकाल के दौरान उसकी पत्नी की मृत्यु, वसीयतकर्ता द्वारा अपने जीवन काल के दौरान स्वयं गोद लेने में विफलता, और वसीयतकर्ता से पहले गोद लिए गए व्यक्ति की मृत्यु। यदि अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया गया तो खंड के पहले भाग को दो भागों में विभाजित करना होगा और इसे वसीयतकर्ता या उसकी पत्नी की गोद लेने में विफलता को कवर करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति "मैं और मेरी पत्नी" को "मैं या मेरी पत्नी" के रूप में पढ़ा जाना होगा, और इस संदर्भ में यह अनुचित लगता है। यह तर्क कि वसीयतकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा संयुक्त रूप

से गोद नहीं लिया जा सकता, हमारी राय में, बहुत अकादमिक और तकनीकी है। यह बिल्कुल सच है कि हिंदू कानून के तहत गोद लेना जरूरी है और वसीयतकर्ता को गोद दिया जा सकता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अगर वसीयतकर्ता ने अपने जीवनकाल के दौरान गोद लिया होता तो उसकी पत्नी भी उसमे शामिल होती और इसमें कोई संदेह नहीं है हिंदू कानून उस अर्थ में एक दत्तक मां (प्रतिग्राहित्री माता (मेने ऑन हिंदू लॉ इट यूसेज, 11वें संस्करण, पृष्ठ 244, 245)) को मान्यता देता है। (देखें: अन्नपूर्णी नाचियार बनाम फोर्ब्स ((1899) 26 आईए 246, 253)। इसलिए, यह तर्क देना उचित नहीं लगता कि चूंकि पति और पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से गोद लेना हिंदू कानून के लिए अज्ञात है, इसलिए प्रासंगिक खंड में "और" शब्द को "या" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार करने में यही पहली कठिनाई है।

दूसरी कठिनाई यह है कि यदि शब्द "और" को "या" के रूप में पढ़ा जाता है तो वसीयतकर्ता द्वारा अकेले ही लड़के को गोद लेने के खंड के पहले भाग में विचार किया गया तीसरा मामला अनावश्यक होगा। वसीयतकर्ता द्वारा अकेले कार्य करते हुए गोद लेना पहले से ही खंड के पहले भाग में शामिल है। श्रीमान शास्त्री ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि यह अतिशयता उनके निर्माण पर प्रभाव डालेगी; लेकिन, उन्होंने तर्क दिया, जरूरी नहीं कि यह उनके निर्माण को विफल कर दे।

उक्त निर्माण को स्वीकार करने में तीसरी कठिनाई यह है कि जो अधिकार पहले से ही प्रतिवादी 5 में खंड 11 के तहत निहित है, वह खंड 12 द्वारा फिर से निहित है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, खंड 11 के तहत प्रतिवादी 5 को वसीयतकर्ता और उसके मृत चचेरे भाई थायुमानस्वामी पिल्लई के बीच समझौते के अनुसरण में आधी संपत्ति दी गई थी। इसलिए, खंड 12 के तहत एक बार फिर से प्रतिवादी 5 के पक्ष में कोई निर्णय देने का शायद ही कोई अवसर या आवश्यकता है। इस कठिनाई की

उपस्थिति पर भी कोई विवाद नहीं है। इस कठिनाई के संबंध में एकमात्र तर्क यह था कि 'एक प्रचुर सावधानी के रूप में वसीयतकर्ता ने प्रतिवादी 5 के पक्ष में वसीयत दोहराई, हालांकि उक्त वसीयत पूरी तरह से खंड 11 के तहत प्रदान की गई थी।

अपीलकर्ता के आग्रह को स्वीकार करने में अभी भी एक और कठिनाई है, और वह खंड 12 के अंतिम भाग के संबंध में है। इस खंड के तहत, यदि वसीयतकर्ता और उसकी पत्नी बिना गोद लिए मर जाते हैं और यदि कल्याणसुंदरम की मृत्यु उनसे पहले हो जाती है तो प्रतिवादी 2 और 3 को सारी संपत्ति मिल जाएगी और खंड में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अपने जीवनकाल के दौरान वे उनका आनंद लेंगे। अब, यह स्पष्ट है कि यदि अभिव्यक्ति "सभी गुण" का अर्थ है, जैसा कि होना चाहिए, बिना किसी अपवाद के सभी, तो फिर प्रतिवादी 5 में जो पहले से ही निहित है वह इस खंड द्वारा विनिवेशित कर दिया जाता है यदि वह वसीयतकर्ता के बाद लेकिन उसकी विधवा से पहले मर जाता है और उनमें से किसी ने भी गोद नहीं लिया है, और यह खंड 11 के साथ स्पष्ट रूप से असंगत होगा। इस कठिनाई का सामना करते हुए श्री शास्त्री ने सुझाव दिया कि संदर्भ की आवश्यकता है कि "सभी संपत्तियों" का अर्थ उन सभी संपत्तियों से होगा जो अपीलकर्ता के पास चली जातीं यदि उसे अपनाया गया होता; यानी, गोद लेने के आधार पर उन्हें धारा 11 के तहत आधी संपत्ति दी गई। "सभी संपत्तियों" शब्दों के अर्थ पर ऐसी सीमा हमें पूरी तरह से अनुचित लगती है। इसलिए, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि खंड 11 और 12 को पढ़ते हुए उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि खंड 12 का उद्देश्य वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय लागू होना था, बाद में नहीं और कि अपीलकर्ता को खंड 12 के तहत अधिकार तभी मिलेगा जब वसीयतकर्ता की विधवा की मृत्यु वसीयतकर्ता से पहले हो चुकी हो और उसकी मृत्यु से पहले वसीयतकर्ता द्वारा कोई गोद न लिया गया हो। यदि ऐसा है, तो अपीलकर्ता खंड 12 के बल पर किसी भी अधिकार या स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि प्रासंगिक समय में इसको

लागू करने का इरादा ही नहीं था। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता के अधिकार केवल खंड 11 के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और वे अधिकार तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकते जब तक कि उसे प्रतिवादी 1 द्वारा गोद नहीं लिया जाता। उस दृष्टिकोण पर निर्वसीयत और निहित होने का स्थगन की संभावना है; लेकिन उसे टाला नहीं जा सकता। निचली अदालतों द्वारा यही दृष्टिकोण अपनाया गया है, और अपीलकर्ता की ओर से श्री शास्त्री द्वारा हमारे सामने पेश किए गए तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद हमें उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

परिणाम यह होता है कि अपील विफल हो जाती है; लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।